भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1012

(जिसका उत्तर मंगलवार, 29 जुलाई, 2025/7 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

पीएम इंटर्नशिप योजना

1012. श्री नीरज डांगीः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को कितना मासिक वेतन दे रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए किन-किन क्षेत्रों में इंटर्नशिप को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को इस योजना के एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत की, जिसका लक्ष्य एक वर्ष में युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के पहले दौर में, भागीदार कंपनियों ने देश भर में पीएमआईएस पोर्टल पर 1.27 लाख से ज़्यादा इंटर्नशिप के अवसर जारी किए। इसके प्रति, लगभग 1.81 लाख अभ्यार्थियों से 6.21 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए। 3.23 लाख से ज़्यादा आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करके आगे के चयन के लिए कंपनियों को भेजा गया।

9 जनवरी, 2025 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे दौर में, लगभग 327 भागीदार कंपनियों ने देश के 735 जिलों में 1.18 लाख से ज़्यादा इंटर्नशिप अवसर (नए और पिछले दौर के संपादित अपूरित अवसर) जारी किए हैं। इस दौर में 2.14 लाख से ज़्यादा आवेदकों में से 4.55 लाख से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए। इस दौर में, 3.05 लाख से ज़्यादा आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया गया और आगे के चयन के लिए कंपनियों को भेजा गया। वर्तमान में, ऑफर जारी करने और इंटर्न द्वारा स्वीकरण/ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जारी है।

पायलट परियोजना के पहले और दूसरे दौर के अंतर्गत चयनित आवेदनों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(ख): पायलट परियोजना के अंतर्गत, इंटर्नशिप स्थल पर इंटर्नशिप शुरू करने पर, सरकार द्वारा प्रत्येक इंटर्न को ₹6,000 का एकमुश्त आकस्मिक अनुदान दिया जाता है, जो कंपनी द्वारा सत्यापन के अधीन होता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी, इंटर्न की उपस्थिति और संबंधित कंपनी नीतियों के आधार पर, हर महीने अपने सीएसआर फंड से प्रत्येक इंटर्न को ₹500/- जारी करती है। एक बार जब कंपनी भुगतान कर देती है, तो सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रशिक्षुओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रति माह 4,500 रुपये जारी करती है।

(ग): साझेदार कंपनियां विमानन और रक्षा, ऑटोमोटिव, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, रासायनिक उद्योग, तेल, गैस और ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे विविध क्षेत्रों में बड़ी संख्या में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर रही हैं और बिक्री, लेखांकन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रक्रिया सहयोगी, विनिर्माण सहयोगी और संयंत्र संचालन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भूमिकाएं प्रदान कर रही हैं।

देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की समावेशिता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल (पोर्टल) 12 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय इस योजना के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मंत्रालय देश भर के लक्षित समूहों तक पहुँचने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप भी चला रहा है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1012 भाग (क) का अनुलग्नक
पीएमआईएस पायलट परियोजना के राउंड-I और राउंड-II में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से चयनित आवेदनों की संख्या।

क्र.सं.	राज्य	चयनित आवेदनों की संख्या	
		राउंड I	राउंड II
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	47	29
2	आंध्र प्रदेश	33072	47870
3	अरुणाचल प्रदेश	88	65
4	असम	13620	5815
5	बिहार	21685	20044
6	चंडीगढ़	362	205
7	छत्तीसगढ	8031	11089
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	107	68
9	दिल्ली	8812	4602
10	गोवा	91	192
11	गुजरात	14484	10062
12	हरियाणा	21780	5348
13	हिमाचल प्रदेश	2522	1102
14	जम्मू और कश्मीर	3098	3690
15	झारखंड	8217	4176
16	कर्नाटक	12725	10071
17	केरल	7500	5510
18	लद्दाख	70	45
19	लक्षद्वीप	0	2
20	मध्य प्रदेश	30728	30088
21	महाराष्ट्र	12994	20800
22	मणिपुर	249	102
23	मेघालय	146	139
24	मिजोरम	20	6
25	नगालैंड	167	73
26	ओडिशा	13013	32279
27	पुदुचेरी	401	219
28	पंजाब	2206	6067
29	राजस्थान	16336	22093
30	सिक्किम	37	78
31	तमिलनाडु	9344	8546
32	तेलंगाना	19037	18797
33	त्रिपुरा	779	2178
34	उत्तर प्रदेश	47993	25584
35	उत्तराखंड	2157	1299
36	पश्चिम बंगाल	11347	7355
कुल योग		**323265**	**305688**